सिग्नेचर ब्रिज की डिजाइन फाइनल

रेलमंत्री ने कहा- यह होगा देश का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज

काशी में बढ़ेंगी ट्रेनें, सिग्नेचर ब्रिज से यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा

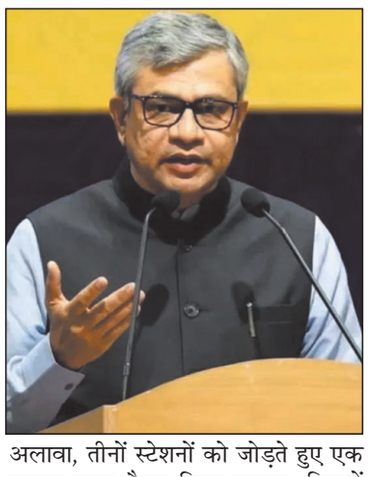

वाराणसी, 9 नवंबर. रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी स्थित बनारस, वाराणसी और काशी रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया और विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने मालवीय पुल पर बनने वाले सिग्नेचर ब्रिज की डिजाइन को फाइनल करने की जानकारी दी.

यह ब्रिज चार रेलवे लाइन और छह लेन की सड़क के साथ बनेगा और इसे देश का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बताया गया है. रेलमंत्री ने कहा कि ब्रिज निर्माण में ऐसा ध्यान रखा जाएगा कि हाईवे पर यात्रा कर रहे लोगों को कोई असुविधा न हो. इसके अलावा, तीनों स्टेशनों को जोड़ते हुए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा.

वाराणसी रेलवे स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना है, जो बड़े त्योहारों और कार्यक्रमों के दौरान यात्रियों के लिए मददगार साबित होगी.

> रेलमंत्री ने निरीक्षण के दौरान रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की स्थिति भी जानी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टेशनों पर चल रहे विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए. उन्होंने निर्माण कार्यों से जुड़े मॉडल का भी अवलोकन किया. विशेषज्ञों का कहना है कि सिग्नेचर ब्रिज न केवल काशी क्षेत्र के रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगा, बल्कि यात्रियों और सड़क उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए यातायात और यात्रा अनुभव में सुधार लाएगा. यह परियोजना शहर के औद्योगिक और पर्यटन विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी.

कोल इंडिया के सीएमडी ने शेयर के 440 तक पहुंचने का अनुमान जताया

नई दिल्ली, 09 नवम्बर. कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सनोज कुमार झा ने कंपनी के भविष्य और शेयर प्रदर्शन को लेकर आशावादी संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी इस वित्त वर्ष में 87.5 करोड़ टन कोयला उत्पादन लक्ष्य हासिल करने या उसके करीब पहुंचने का प्रयास करेगी. यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीआईएल पिछले दो महीनों में अपने उत्पादन लक्ष्य से चूक गई थी. झा ने बताया कि मानसून की अनियमित बारिश और बिजली क्षेत्र में धीमी मांग के कारण सितंबर और अक्टूबर में उत्पादन अपेक्षित स्तर से कम रहा. सितंबर में कंपनी का उत्पादन घटकर 4.89 करोड़ टन और अक्टूबर में 5.64 करोड़ टन रह गया.

इंडियन ओवरसीज बैंक की नई सुविधा

फीचर फोन यूजर्स के लिए डिजिटल भुगतान का आसान समाधान

नई दिल्ली, 9 नवंबर. डिजिटल भुगतान अब बिना इंटरनेट के भी संभव हो गया है. सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआई 123 पे नामक नई सेवा शुरू की है, जिससे लोग केवल मिस्ड कॉल के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे.

यह सुविधा खास तौर पर उन 400 मिलियन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास इंटरनेट-सक्षम स्मार्टफोन नहीं हैं. आईओबी ने यह सुविधा एनपीपीएसटी (नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड) के सहयोग से लॉन्च की है. यूपीआई 123 पे में यूजर्स मिस्ड कॉल देने के बाद आईभीआर कॉल के जरिए अपने ट्रांजैक्शन की राशि दर्ज कर सकते हैं और अपना यूपीआई पीआईएन डालकर पेमेंट पूरा कर सकते हैं. यह पूरी प्रक्रिया वॉइस कमांड या कीपैड इनपुट के जरिए की जा सकती है. इस नई सेवा के तहत यूजर्स 12 भारतीय भाषाओं में पेमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा, उपयोगकर्ता अपने बैंक बैलेंस की जानकारी देख सकते हैं, पिछले 5 ट्रांजैक्शन का विवरण प्राप्त कर सकते हैं, यूपीआई पीआईएन बदल सकते हैं और किसी भी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं. आईओबी का यह कदम डिजिटल इंडिया को और मजबूत बनाने और डिजिटल भुगतान को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है. देश में अभी भी करोड़ों लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और यूपीआई 123 पे इस अंतर को कम करने का प्रयास करेगा.

विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट

689 .73 अरब डॉलर पर पहुँचा स्तर

मुंबई, 09 नवंबर. देश का विदेशी मुद्रा भंडार 31 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 5.623 अरब डॉलर घटकर 689.733 अरब डॉलर रह गया और इससे लगातार तीन सप्ताह की गिरावट में विदेशी मुद्रा भंडार 21.869 अरब डॉलर घट चुका है.

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में यह 6.925 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 695.355 अरब डॉलर पर रहा था. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 07 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, गत 31 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 1.957 अरब डॉलर घटकर 564.591 अरब डॉलर रह गया. इसमें अमेरिकी डॉलर के अलावा जापानी येन, यूरो और ब्रितानी पाउंड को शामिल किया जाता है. डॉलर के सापेक्ष विनिमय दर के आधार पर इनका मूल्य तय होता है. आलोच्य सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 3.81 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 101.726 अरब डॉलर पर आ गया. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि 16.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.772 अरब डॉलर पर और विशेष आहरण अधिकार 1.9 करोड़ डॉलर की गिरावट के साथ 18.644 अरब डॉलर पर रहा.

सुजुकी मोटर गुजरात का मर्जर मारुति सुजुकी इंडिया के साथ

नई दिल्ली/मुंबई, 9 नवंबर. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने मारुति सुजुकी इंडिया और सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है. दिल्ली स्थित दो सदस्यीय पीठ ने दोनों कंपनियों की याचिका को स्वीकृत करते हुए कहा यह योजना सभी संबंधित पक्षों—शेयरधारकों, लेनदारों और कर्मचारियों—के हित में है. एनसीएलटी ने आदेश में बताया कि आयकर विभाग, अधिकारिक परिसमापक अहमदाबाद, आरबीआई, सेबी, बीएसई और एनएसई ने इस विलय योजना पर कोई आपत्ति नहीं जताई. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष रामलिंगम सुधाकर और सदस्य रवींद्र चतुर्वेदी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत इस विलय को मंजूरी दी.

गेहूं-चावल और तेलों में गिरावट

मांग घटने से खाद्य तेलों पर दबाव, मूंगफली तेल अपवाद रहा मजबूत

चावल-गेहूं के दाम फिसले, उड़द और मसूर में रही मामूली तेजी

> सप्ताह के दौरान गेहूं और आटा की कीमतों में क्रमश- 14 रुपये और छह रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गयी. गेहूं दड़ा 2860 रुपये से घट कर 2836 रुपये प्रति क्विंटल और आटा 3319 से घट कर 3313 रुपये प्रति 100 किलों के भाव दर्ज किया गया. चावल और गेहूं जैसी जिंसों में नरमी का असर खाद्य मुद्रास्फीति पर भी झलक सकता है. इस दौरान वैश्विक बाजार में नरमी के रुख के बीच स्थानीय बाजार में दालों में मिला जुला रुख दिखा. उड़द और मसूर के भाव सप्ताह के दौरान कुल मिला कर चढ़े हुए थे जबकि चना, तूअर और मूंग में नरमी का रुख दिखा.

नयी दिल्ली, 9 नवंबर. दिल्ली की थोक मंडियों में शनिवार को समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान चावल, गेहूं, आटा और मूंगफली को छोड़ कर अन्य खाद्य तेलों में मांग की तुलना में स्टॉक की स्थिति अच्छी होने से गिरावट रही. इस दौरान दाल दलहनों में मिला जुला रुख देखा गया जबकि मूंगफली को छोड़ कर अन्य खाद्य तेलों में गिरावट दर्ज की गयी.

देश में चावल की आपूर्ति की स्थिति के मजबूत बने रहने के बीच स्थानीय बाजार में सामान्य स्तर के चावल की दरों में सप्ताह के दौरान नरमी दर्ज की गयी. औसत श्रेणी के चावल का भाव सप्ताहांत 3742 रुपये क्विंटल था जो इससे पिछले सप्ताहांत 3826 रूपये क्विंटल के आस पास था. इस तरह इसके थोक भावों में सप्ताह के दौरान 84 रुपये की गिरावट दर्ज की गयी है. भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और कुल वैश्विक उत्पादन में करीब एक तिहाई योगदान करता है. पिछले एक दशक से भी अधिक समय से भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है और विश्व बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने दिल्ली में चावल पर बड़ा वैश्विकआयोजन किया गया था.

निवेशकों की नजर अब बिहार चुनाव नतीजों पर

नयी दिल्ली, 9 नवंबर. घरेलू अर्थव्यवस्था के बुनियादी संकेत मजबूत बने रहने के बावजूद वैश्विक हालात में अनिश्चितता तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से बिकवाली का दबाव बने रहने से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गत शुक्रवार को समाप्त हुए सप्ताह में गिरावट का सिलसिला बना रहा.

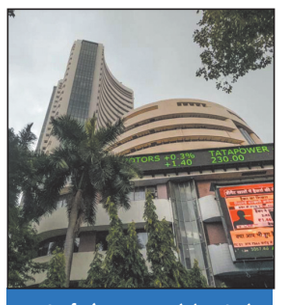

महंगाई और व्यापार घाटे के आंकड़े तय करेंगे अगले सप्ताह की दिशा

बुनियादी संकेत मजबूत, बाजार में सुधार की संभावना

आगामी सप्ताह में बाजार की नजर बिहार विधान सभा चुनाव के नतीजों, खुदरा और थोक महंगायी दर तथा व्यापार घाटे के आंकड़ों बैंकों से कर्ज उठाव की रिपोर्ट और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर टिकी रहेगी. बाजार विश्लेषकों की राय में बाजार में बुनियादी तौर पर मजबूती की धारणा है पर उसे भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता तथा भारत-चीन के बीच व्यापार की आगे की परिस्थितियों को लेकर सकारात्मक खबरों का भी इंतजार है. व्यापार वार्ता के बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हाल के बयानों से बाजार की उम्मीद जगी है कि अमेरिका के साथ कोई अच्छा समझौता हो जाएगा. सप्ताह के दौरान कुछ प्रमुख शेयरों में ऊंचे भाव पर मुनाफा काटने की जल्दी और विदेशी संस्थागत निवेशकों के बराबर बिकवाल बने रहने से जारी गिरावट के बीच बीसई का बीएसई30 सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 करीब 0.9 प्रतिशत दायरे में नीचे आ गये.

भारत की स्थिति मजबूत

वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है और पिछले कुछ समय में निफ्टी में 700 और मिडकैप में 1000 अंक की गिरावट के चलते इस समय भारतीय शेयर बाजार अपने जैसे दूसरे बाजारों की तुलना में और निवेश के लिए और आकर्षक बताया जा रहा है. तिमाही वित्तीय रिपोर्ट के इस सीजन में मिड और स्माल कैप के परिणाम भी तुलनात्मक रूप से अच्छे रहे हैं. अक्टूबर का पीएमआई डाटा उम्मीद से अच्छा रहा तथा कंपनियों के सितंबर तिमाही के लाभ के आंकड़े भी कुल मिला कर संतोषजनक रहे. जीएसटी में कटौती से बाजार में मांग को प्रोत्साहन मिला है. इस तरह कुल मिला कर परिदृश्य उत्साहजनक बना हुआ है.

27 नवम्बर 26 तक अस्थायी निलंबन की घोषणा

अमेरिका-चीन व्यापार समझौते में दोहरे उपयोग वाले तत्वों को मिली राहत

चीन ने गैलियम-जर्मेनियम पर अमेरिका के निर्यात प्रतिबंध हटाया

> यह कदम अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में हुए व्यापार और आर्थिक समझौते का हिस्सा है, जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया के बुसान में मुलाकात के बाद की थी. इस समझौते के तहत चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर लगे जवाबी टैरिफ हटाने, सोयाबीन, ज्वार और लकड़ी की बड़ी मात्रा में खरीद फिर से शुरू करने और अमेरिकी कंपनियों की सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर जांच खत्म करने पर सहमति दी है.

बीजिंग/वॉशिंगटन, 09 नवम्बर. चीन ने अमेरिका के लिए गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक तत्वों पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है. चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को यह घोषणा की.

यह निर्णय विशेष रूप से दोहरे उपयोग वाले वस्तुओं पर लागू नियंत्रण उपायों के आंशिक निलंबन से जुड़ा है और नौ नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा. मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह अस्थायी राहत केवल दूसरी धारा के तहत लाइसेंस और समीक्षा से जुड़ी पाबंदियों पर लागू होगी. पहली धारा, जिसमें अमेरिकी सैन्य या सैन्य उपयोग के लिए दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर रोक है, पहले की तरह लागू रहेगी.

टीटागढ़ रेल का वर्क ऑर्डर और डिविडेंड अपडेट

मुंबई/नई दिल्ली, 9 नवंबर. रेलवे सेक्टर में निवेशकों के लिए उत्साहजनक खबर है. पास अब कुल 30,000 करोड़ का काम है, जिसमें हाल ही में मुंबई मेट्रो लाइन के लिए 2481 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है. यह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए दिया गया है. कंपनी भारतीय रेलवे वैगन मार्केट की अगुआ है और इसका मार्केट शेयर 25 प्रतिशत है. वित्त वर्ष 2025 में कुल 41,929 वैगन का उत्पादन हुआ.

डिजिटल गवर्नेंस में डिजीलॉकर ने बढ़ाया विश्वास और दक्षता

नयी दिल्ली, 9 नवंबर. पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र और जरूरी सूचनाओं को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की डिजलॉकर सुविधा पर राजधानी में हुए एक सम्मेलन में कागजरहित कामकाज, समावेशी शिक्षा और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं को सुविधाजनक बनाने में इस की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित किया गया.

सम्मेलन में कहा गया है कि डिजीलॉकर ने डिजिटल व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने में बड़ा योगदान किया है और यह देश में डिजिटल ट्रस्ट क्रांति में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. डिजीलॉकर-सभी के लिए पेपरलेस एक्सेस को सक्षम बनाना विषय पर भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में डिजीलॉकर को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान करने वाले राज्यों को सम्मानित भी किया गया. मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि डिजीलॉकर नागरिकों, मंत्रालयों और विभागों को जोड़ने वाली ट्रस्ट लेयर के रूप में काम करता है.

समाचार विशेष

नवंबर क्रांति या दिसंबर रिवॉल्यूशन

दिल्ली में डीके शिवकुमार ने क्यों डाला डेरा?

नई दिल्ली. कर्नाटक की राजनीति में नवंबर क्रांति का शोर अब दिल्ली तक पहुंच गया है. कांग्रेस में बदलाव की अटकलों के बीच उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राजधानी में डेरा डालकर पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है. जब उनसे नवंबर क्रांति की बात पूछी गई, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, न नवंबर क्रांति है, न दिसंबर रिवॉल्यूशन. अगर असली क्रांति होगी तो वह 2028 में होगी, जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी.

शिवकुमार का यह बयान न सिर्फ अफवाहों को जवाब देता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि वे अब भी आलाकमान की लाइन पर ही चल रहे हैं. वहीं भाजपा और विपक्ष ने इन बयानों को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया है. दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि नवंबर या दिसंबर क्रांति जैसी बातें राजनीतिक कल्पना मात्र हैं. उन्होंने कहा, यह किसी की लिखी कहानी है. हमें बिहार चुनाव समेत कई जिम्मेदारियां दी गई हैं, और हम उन्हें पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर किसी प्रकार की बगावत या सत्ता परिवर्तन जैसी कोई चर्चा नहीं है.

मंत्रिमंडल विस्तार पर तोड़ी चुप्पी- एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के सवाल पर शिवकुमार ने कहा, मैं किसी से नहीं मिलना.

मंत्रिमंडल विस्तार पर मुझसे कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि वह पार्टी अनुशासन के सिपाही हैं और पार्टी की सीमा से बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता. कैबिनेट विस्तार और नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर डीके शिवकुमार ने कहा, यह सब आपकी कल्पना है. पार्टी जो भी फैसला करेगी, हम उसी का पालन करेंगे. मुख्यमंत्री पद को लेकर भी उन्होंने कहा, अगर कार्यकाल पांच साल का है तो पांच साल, अगर दस साल का है तो दस साल- फैसला हाईकमान का होगा.

मंत्री पद के इच्छुकों को संदेश

शिवकुमार ने उन नेताओं को भी अप्रत्यक्ष संदेश दिया जो मंत्री पद की आस लगाए बैठे हैं. उन्होंने कहा, यह दिल्ली के नेताओं का मामला है, वे तय करेंगे कि कब और कैसे फैसला लेना है. उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि वे किसी गुटबाजी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के साथ ही आगे बढ़ेंगे. हालांकि डीके शिवकुमार के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि क्रांति जैसी कोई तात्कालिक हलचल नहीं है. लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे 2028 की तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

वोटिंग उत्साह ने दुनिया का खींचा ध्यान

देश की राजनीति और आगामी चुनावों के समीकरण बदलने के संकेत

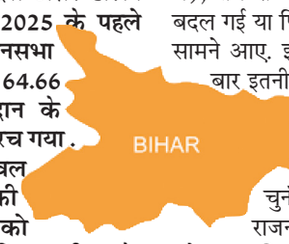

पटना. भारत के राजनीतिक नक्शे पर हमेशा असर डालने वाला बिहार 2025 के पहले चरण के विधानसभा चुनाव में 64.66 प्रतिशत मतदान के साथ इतिहास रच गया. यह वृद्धि न केवल राज्य की राजनीति को हिला रही है बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक राजनीतिक विश्लेषकों की भी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं.

इतिहास में जब भी बिहार में 60 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ (1990, 1995 और 2000 में), तब राज्य की सत्ता या तो बदल गई या फिर खिचड़ी नतीजे सामने आए. इस बार भी पहली बार इतनी बड़ी भागीदारी ने एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए रणनीतिक चुनौती पैदा कर दी है. राजनीतिक विशेषज्ञ सुरेन्द्र अग्निहोत्री और प्रो. रविकांत पाठ मान रहे हैं कि बिहार के चुनाव परिणाम अन्य राज्यों में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की दिशा भी तय कर सकते हैं.

'सिक्रेट वोटर' की निर्णायक भूमिका

महिला मतदाता लगातार बढ़ रही भागीदारी के साथ निर्णायक भूमिका निभा रही हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हें 'सिक्रेट वोटर' बताया है. एनडीए उम्मीद कर रही है कि महिला सशक्तिकरण योजनाओं और रोजगार पैकेज का लाभ उन्हें चुनावी मोर्चे पर मिलेगा. जबकि महागठबंधन युवाओं और महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति पर जोर दे रहा है.

थरूर के लिए अब कांग्रेस में जगह नहीं

तिरुवनंतपुरम. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस की दुखती नस दबा दी है. अब तक वे राजनीतिक और नीतिगत मसले पर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे लेकिन अब उन्होंने वंशवाद का मुद्दा उठा दिया है. थरूर ने कहा है कि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है.

केरल की तिरूवनंतपुरम सीट से कांग्रेस के चार बार के सांसद शशि थरूर इतने पर नहीं रूके. उन्होंने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार के कारण यह विचार भारत की राजनीति में स्थापित हुआ कि राजनीतिक नेतृत्व जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है. इस तरह से उन्होंने देश की सभी प्रादेशिक पार्टियों में चल रही वंशवादी राजनीति के लिए नेहरू-गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया है.

शशि थरूर ने 'प्रोजेक्ट सिंडिकेट' की ओर से 31 अक्टूबर को प्रकाशित लेख में यह भी कहा है कि दशकों से एक परिवार राजनीति के शीर्ष पर बना हुआ है. इससे पहले थरूर जो कुछ कह या कर रहे थे उसकी माफी थी लेकिन इसकी माफी नहीं है कि उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार को निशाना बनाया, वंशवाद पर सवाल उठाया और देश में वंशवादी राजनीति की जड़ें मजबूत करने में सोनिया और राहुल गांधी के परिवार का हाथ बताया. यह निर्णायक क्षण है. ऐसा लग रहा है कि थरूर ने भी समझ लिया है कि अब कांग्रेस में दिन पूरे हो गए हैं. यह भी कहा जा रहा है अब बिहार चुनाव खत्म होने वाला है और भाजपा का फोकस केरल पर बन गया है और उसमें थरूर की भूमिका दिख रही है. कई जानकार लोग यह भी कह रहे हैं कि तिरूवनंतपुरम सीट पर विधानसभा के साथ उपचुनाव हो सकता है. अगले कुछ दिन में स्थिति साफ होगी.

विशेष | **अजित नाराज, झिरवल-कोकाटे और भुजबल को लगाई फटकार**

किस काम के हो मंत्री?

मुंबई. महाराष्ट्र स्थानीय निकायों के चुनावों की पृष्ठभूमि में महायुति सरकार में शामिल उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपनी पार्टी के नेताओं में नई ऊर्जा भरने के लिए मैराथन समीक्षा बैठकें कर रहे हैं. इसी दौरान डीसीएम अजित पार्टी के मंत्रियों, विधायकों, नेताओं एवं पदाधिकारियों के काम की समीक्षा कर रहे हैं.

मुंबई में इसी संदर्भ में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने विधायकों और कुछ मंत्रियों के निराशाजनक प्रदर्शन के बारे में खुलकर नाराजगी व्यक्त की. खासकर नाशिक जिले से संबंध रखने वाले मंत्री छगन भुजबल, माणिकराव कोकाटे एवं नरहरी झिरवल के संबंध में व्यक्त की गई अजित की नाराजगी बुधवार को महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गई. राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनावों का शंखनाद कर दिया. इसी के साथ राज्य के सियासी दलों ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है. मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों और प्रमुख नेताओं अजित पवार की एक बैठक हुई. बैठक में आगामी चुनावों और महायुति पर मंथन किया गया लेकिन इस दौरान कुछ पदाधिकारियों ने मंत्रियों एवं विधायकों के निष्क्रियता की शिकायत की. इसके बाद डीसीएम ने संबंधित मंत्रियों का नाम लेकर नाराजगी जताई. नाशिक जिले से ताल्लुक रखने वाले मंत्रियों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में 3 मंत्री हैं लेकिन पार्टी के लिए तीनों अनुपयोगी सिद्ध हुए हैं. इन्होंने जिले में पार्टी के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है.

तीनों से पूछे सवाल- नाशिक जिले से एनसीपी (अजित पवार) के 3 मंत्री है. मंत्री छगन भुजबल, खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे और खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवल, बीमार होने की वजह से भुजबल तो बैठक में नहीं आए थे लेकिन कोकाटे और झिरयल से अजित ने पूछ लिया कि उन्होंने पार्टी के विकास के लिए कौन-सा कार्यक्रम आयोजित किया था या कार्यकर्ताओं के बुलावे पर किन कार्यक्रमों में शामिल हुए थे?

स्थानीय पदाधिकारियों ने की शिकायत

एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं तो माणिकराव कोकाटे खेल मंत्री और नरहरी झिरवल के पास खाद्य एवं औषधि प्रशासन जैसा महत्वपूर्ण विभाग है. इसके अलावा मंत्री कोकाटे नंदुरबार जिले के पालक मंत्री हैं तथा मंत्री झिरवल हिंगोली जिले के पालक मंत्री हैं. स्थानीय पदाधिकारियों की शिकायत थी कि ये मंत्री अपने जिले में आते ही नहीं हैं. इस पर अजित ने खेद व्यक्त करते हुए गुस्से में कहा कि आपसे पार्टी को क्या लाभ मिल रहा है?